>

Title: Issue regarding Andaman Trunk road in Andaman & Nicobar Island.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अग्रवाल जी ने दिल्ली के बारे में अपनी बात कही है कि अनएथोराज्ड कॉलोनीज़ को फरवरी, 2007 से रैगूलराइज किया गया। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से दिल्ली में अनएथोराइज्ड कॉलोनीज़ को रैगूलराइज़ किया, उसी तरह से अण्डमान में भी करे।

महोदय, जिसके लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं वह अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह की कांग्रेस सरकार और उनका मुखिया नेशनल एडवाइज़री काउंसिल का चैयरपर्सन वर्ष 2006 में अण्डमान की लाइफ लाइन, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था, हाल ही में 17 अक्टूबर, 2012 को प्रशासन ने यह प्रस्ताव पेश किया कि अण्डमान ट्रंक रोड़ को जारवा के नाम पर हम बंद कर देंगे। आइये हम इसका इतिहास ढूंढते हैं। अण्डमान में जब ब्रिटिश आए थे तो उस समय भारत के विभिन्न प्रांतों से कुछ लोगों को लाकर अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में बैठाया गया था। उसके बाद सैटलमेंट का ज़माना आया। बांग्लादेश, तमिलनाडु, श्री लंका और झारखण्ड से रिफ्यूज़ी लोग लाए गए, जिन्हें मिडिल और नार्थ अण्डमान में बैठाया गया। आप जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर बीच में है और आप यह भी जानते हैं कि भारत के दो द्वीप थे, छोटा कोको आईलैण्ड और बड़ा कोको आईलैण्ड। पचास साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोको द्वीप को बर्मा को गिफ्ट कर दिया। बर्मा के पास जाने के बाद कोको आईलैण्ड में चीन का अड्डा बन गया है। उसी का लाइफ लाइन है मिडिल और नार्थ अण्डमान। उस ज़माने में पोर्ट ब्लेयर से मिडिल-नार्थ जाने के लिए समुद्र का एक पथ था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लोगों ने मांग की और इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के समय अण्डमान ट्रंक रोड़ बनाने का प्रस्ताव लाया गया। इसका काम वर्ष 1958 में शुरू किया। काम चलता रहा। बीच में 43 किलोमीटर का जारवा रिजर्व एरिया आ गया। वर्ष 1975 में काम बंद हो गया। फिर दुबारा कांग्रेस राज्य सरकार में थी। वर्ष 1987 में दोबारा काम शुरू किया। वर्ष 1998 में अण्डमान ट्रंक रोड का दोबारा काम पूरा हुआ। पोर्ट ब्लेयर से बडाटंग का जो बोट रूट था, वह ऑटोमेटिक बंद हो गया। लोग समुद्र के रास्ते से उल्टी के डर से जाना नहीं चाहते। यह सब चलता रहा। इसी बीच वर्ष 2004 में वाजपेयी सरकार आयी। उसी रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया। इसके बीच में इस कांग्रेस सरकार जारवा के नाम पर अण्डमान को तबाह करने के लिए एक प्लान बनाया। इन्होंने यह प्रस्ताव किया कि जारवा एरिया अण्डमान ट्रंक रोड के बीच में आ रहा है। 43 किलोमीटर के रोड के एरिया को बीच में बंद करके पोर्ट ब्लेयर से बड़ाटंग समुद्र के पथ में अल्टरनेट सी-रूट बनाया, तथा एटीआर बंद करेंगे । इसकी शुरूआत आदिवासी मंत्रालय से हुई। 11 मई, 2009 को दिल्ली शहर में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में एक मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने कहा कि जारवा एरिया के बीच में रोड जो गया है, इस रोड से जारवा के साथ लोगों का, टुरिस्टों का संबंध जुड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए रोड को बंद कर दिया जाए। 17 अक्टूबर, 2012 को प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट सब्मिट किया। यह उसका मैप है, डॉक्यूमेंट है। इसमें प्रशासन ने भारत सरकार को सब्मिट किया कि मार्च 2015 में जो पोर्ट ब्लेयर से बाड़ाटन तक रोड था, इसको बंद करके इसके विकल्प के रूप में एक समुद्र पथ चलाएंगे। इसका परिणाम क्या निकला? आज करीब-करीब दो-ढाई लाख टूरिस्ट पोर्ट ब्लेयर से बाड़ाटन जाते हैं और आगे डिगलीपुर तक जाते हैं। उस रूट पर 2700 गाड़ियां चलती हैं। मिडिल नॉर्थ में टूरिज्म के नाम पर इंवेस्टमेंट्स हुए। वहां ढाई लाख लोगों की आबादी है और सरकार बोल रही है कि हमारे पास 300 जारवा हैं और उन्हें बचाने के नाम पर वे ढाई लाख आबादी का टूरिज्म तथा एटीआर की लाइफ लाइन बंद करेंगे। ये ढाई लाख लोगों की जिंदगी से खेल रही है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि आज जो अनइम्प्लायड लोगों ने लोन लेकर टूरिज्म के लिए गाड़ी लिया, जो बेकार नवयुवकों को इससे काम मिला, आप यह बंद करने जा रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि कांग्रेस सरकार अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह से न खेले। गवर्नमेंट की किताब भी बोलती है कि अगर अण्डमान का नवयुवक विदेशी लोगों के साथ मिल गया तो अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह को और एक माओवादी न बनाए। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जो अण्डमान ट्रंक रोड बनाया गया था, उसको बिल्कुल बंद न करे और अल्टरनेट समुद्र रूट न बनाए। यह मैं चेतावनी दे रहा हूं। इस पर कांग्रेस सरकार ध्यान दे।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : हां।